

विषय :- अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में।

—0—

प्रिय साथी

मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि छ.ग. राज्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु गठित राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक दिनांक 14.07.2017 के दौरान यह तथ्य परिलक्षित हुआ है कि हमारा राज्य वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है तथापि सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता प्रदान करने के क्षेत्र में और अधिक सक्रियता पूर्वक कार्य किए जाने की आवश्यकता है।

छ.ग. राज्य में सामुदायिक वन अधिकार हेतु मार्च 2017 की स्थिति में प्राप्त दावों की तुलना में वितरित मान्यता पत्रों की स्थिति पर गौर किया जाए तो स्पष्ट होता है कि राज्य में 50 प्रतिशत से अधिक सामुदायिक दावे निरस्त किए गए हैं, जो कि बहुत अधिक हैं। इस स्थिति में बदलाव लाया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त निरस्त सामुदायिक प्रकरणों को पुनर्विचार में लेकर निराकृत किए जाने की स्थिति की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि कोरबा, जशपुर एवं विलासपुर जैसे कुछ जिलों के द्वारा निरस्त दावों को पुनर्विचार में लेकर दावे स्वीकृत किए गए हैं किन्तु अन्य जिलों के द्वारा या तो दावे पुनर्विचार में लिए ही नहीं गए हैं या निरस्त दावों की तुलना में बहुत कम संख्या में पुनर्विचार में लिए गए हैं साथ ही पुनर्विचार पश्चात स्वीकृत दावों की संख्या भी बहुत कम है (विस्तृत प्रपत्र संलग्न— परिशिष्ट 1)। अतः सभी जिला कलेक्टर अपने जिले में सामुदायिक वन अधिकार दावों के निरस्तीकरण के कारणों का पता लगाकर उनके निराकरण का प्रयास करें साथ ही समस्त निरस्त सामुदायिक दावों को पुनर्विचार में लेकर परिणामों से शासन को अवगत करावें।

इसके अतिरिक्त यदि राज्य में सामुदायिक वन अधिकारों के अंतर्गत वितरित भूमि का क्षेत्रफल (लगभग 5,63,431 हेक्टेयर) पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र (वितरित भूमि लगभग 17,95,163 हे.) की तुलना में बहुत कम है, जबकि महाराष्ट्र में वितरित सामुदायिक वन अधिकार पत्रों की संख्या छ.ग. की तुलना में आधे से भी कम है (विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट 2 संलग्न है)। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जहां छ.ग. राज्य में धमतरी (1,46,688 हे.) एवं कांकेर (1,21,734 हे.) जैसे कुछ जिलों में इस क्षेत्र में बेहतर कार्य किया है, जो अन्य जिलों के लिए अनुकरणीय हो सकता है, वहीं

बालोद, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, मुंगेली, बस्तर और रायगढ़ जैसे जिलों में सामुदायिक दावों के अंतर्गत वितरित भूमि का रकबा बहुत कम है (विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट 3 संलग्न)। अतः इन जिलों में विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। मैं इस संबंध में यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि सामुदायिक वन अधिकारों के अंतर्गत भूमि वितरण के संबंध में वन अधिकार अधिनियम में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है और अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न सामुदायिक प्रयोजनों हेतु वितरित भूमि का रकबा बढ़ाए जाने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं।

उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन नियम 2012 के उपाबंध 1, प्रारूप 'ख' में—

- धारा 3-1(ख)— निस्तार के रूप में सामुदायिक अधिकार,
- धारा 3-1(ग)— गौण वन उत्पादों पर अधिकार,
- धारा 3-1(छ)— उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय), चराई हेतु, पारंपरिक संसाधनों तक यायावरों और पशुपालकों की पहुंच,
- धारा 3-1(ड)— पीटीजी व कृषि पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास और पूर्ववास/बसाहट (habitat and habitation) की सामुदायिक भूधृति (community tenure),
- धारा 3-1(ट)— जैव विविधता तक बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच का अधिकार,
- धारा 3-1(ठ)— अन्य पारंपरिक अधिकार आदि सामुदायिक वन अधिकारों के लिए ; तथा
- धारा 3-1(झ) के अधीन सामुदायिक वन संसाधन पर अधिकार हेतु उपाबंध 1 के प्रारूप 'ग' में आवेदन/दावे प्राप्त किए जाकर पात्रतानुसार मान्यता संबंधी कार्यवाही की जानी है।

अतः सभी जिला कलेक्टर सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता प्रदान करने हेतु व्यक्तिगत रुचि लेते हुए उपरोक्तानुसार विभिन्न सामुदायिक प्रयोजनों हेतु ग्राम स्तर पर अधिक से अधिक दावे आमंत्रित करावें और पात्रता को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक वन अधिकार दावों की स्वीकृति/वितरण में गति लाएं ताकि छ.ग. राज्य सामुदायिक वन अधिकारों के क्षेत्र में देश में अग्रणी स्थान प्राप्त कर सकें।

**भवदीय**

**(विवेक ढाँड)**

प्रति,

श्री .....

कलेक्टर,

जिला—.....(छ.ग.)

पृ.क./ / / /

रायपुर दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त।
3. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नया रायपुर, छ.ग.।
4. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास।

मुख्य सचिव

छत्तीसगढ़ शासन



छत्तीसगढ़ शासन  
Government of Chhattisgarh

अद्वैशासकीय पत्र क्र. : 1901/cs/2017  
नया रायपुर, दिनांक : 10.08.2017

विषय : अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में।

प्रिय स्वामी,

मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि छग. राज्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु गठित राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक दिनांक 14.07.2017 के दौरान यह तथ्य परिचित हुआ है कि हमारा राज्य वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है तथापि सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता प्रदान करने के क्षेत्र में और अधिक सक्रियता पूर्वक कार्य किए जाने की आवश्यकता है।

छग. राज्य में सामुदायिक वन अधिकार हेतु मार्च 2017 की तारीख में प्राप्त दावों की तुलना में वितरित मान्यता पत्रों की स्थिति पर गौर किया जाय तो स्पष्ट होता है कि राज्य में 50 प्रतिशत से अधिक सामुदायिक दावों निरस्त किए गए हैं, जो कि बहुत अधिक हैं। इस स्थिति में वकालत आया जाना आवश्यक है इसके अतिरिक्त निरस्त सामुदायिक प्रकरणों के पुनर्विचार में उत्तर विभागात्मक किए जाने की स्थिति की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि राज्य में अशांत एवं अशांत जिलों जैसे कुछ जिलों के द्वारा निरस्त दावों को पुनर्विचार में लेकर दावों स्वीकृत किए गए हैं किन्तु अन्य जिलों के द्वारा या तो दावों पुनर्विचार में लिए ही नहीं गए हैं या निरस्त दावों की तुलना में बहुत कम संख्या में पुनर्विचार में लिए गए हैं साथ ही पुनर्विचार पश्चात स्वीकृत दावों की संख्या भी बहुत कम है (विस्तृत तालिका संलग्न- परिशिष्ट 1)। अतः सभी जिला कलेक्टर अपने जिलों में सामुदायिक वन अधिकार दावों के निरस्तीकरण के कारणों का पता लगाकर उचित निराकरण का प्रयास करें साथ ही समस्त निरस्त सामुदायिक दावों को पुनर्विचार में लेकर परिणामों से शासन का अवगत करावे।



// 2 //

इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान में आया है कि राज्य में सामुदायिक वन अधिकारों के अंतर्गत वितरित भूमि का क्षेत्रफल (लगभग 5,63,431 हेक्टेयर) कम है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जहां छ.ग. राज्य में धमतरी में वितरित सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का क्षेत्रफल 1,46,688 हे. हैं एवं कांकेर में वितरित सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का क्षेत्रफल 1,21,734 हे. हैं और इस क्षेत्र में बेहतर कार्य किया है, जो अन्य जिलों के लिए अनुकरणीय हो सकता है, वहीं बालोद, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, मुंगेली, बस्तर और रायगढ़ जैसे जिलों में सामुदायिक दावों के अंतर्गत वितरित भूमि का रकबा बहुत कम है (विस्तृत जानकारी हेतु संलग्न -परिशिष्ट 3 )। अतः इन जिलों में विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि सामुदायिक वन अधिकारों के अंतर्गत भूमि वितरण के संबंध में वन अधिकार अधिनियम में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है और अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न सामुदायिक प्रयोजनों हेतु वितरित भूमि का रकबा बढ़ाए जाने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं।

उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन नियम 2012 के उपाबंध 1, प्रारूप 'ख' CR (Community Rights) में -

- धारा 3-1(ख)- निस्तार के रूप में सामुदायिक अधिकार,
- धारा 3-1(ग)- गौण वन उत्पादों पर अधिकार,
- धारा 3-1(छ)- उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय), चराई हेतु पारंपरिक संसाधनों तक यायावरों और पशुपालकों की पहुंच,
- धारा 3-1(ड)- पीटीजी व कृषि पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास और पूर्ववास/बसाहट (habitat and habitation) की सामुदायिक भूमि (community tenure),



// 3 //

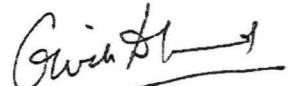
- धारा 3-1(ट)- जैव विविधता तक बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच का अधिकार,
- धारा 3-1(ठ)- अन्य पारंपरिक अधिकार आदि सामुदायिक वन अधिकारों के लिए; तथा
- धारा 3-1(झ)- अंतर्गत CFR (Community Forest Resource) के अधीन सामुदायिक वन संसाधन पर अधिकार हेतु उपाबंध 1 के प्रारूप 'ग' में आवेदन/दावें प्राप्त किए जाकर पात्रतानुसार मान्यता संबंधी कार्यवाही की जानी है।

अतः सभी जिला कलेक्टर सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता प्रदान करने हेतु व्यक्तिगत रूचि लेते हुए उपरोक्तानुसार विभिन्न सामुदायिक प्रयोजनों हेतु ग्राम स्तर पर अधिक से अधिक दावें आमंत्रित करावें और पात्रता को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक वन अधिकार दावों की स्वीकृति/वितरण में गति लाएं ताकि छ.ग. राज्य सामुदायिक वन अधिकारों के क्षेत्र में भी देश में अग्रणी स्थान प्राप्त कर सकें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

रतन-दे,

भवदीय

  
(विवेक ढांड)

प्रति,

समस्त कलेक्टर  
छत्तीसगढ़

परिशिष्ट - 1

बन अधिकार अधिनियम अंतर्गत निरस्त किए गए सामुदायिक दायों के प्रकारों को पुनर्विचार में लिए जाकर निराकृत किए गए प्रकारों की जानकारी

क्र	जिला	निरस्त सामुदायिक प्रकारों की कुल संख्या	निरस्त सामुदायिक प्रकारों में से पुनर्विचार में लिए गए प्रकारों की संख्या	पुनर्विचार में लिए गए सामुदायिक प्रकारों में से स्वीकृत प्रकारों की संख्या	स्वीकृत सामुदायिक प्रकारों में से विधिवत प्रकारों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	गोरखा	40	40	4	4
2	सुपौल	114	92	3	3
3	बलिया	211	211	54	0
4	खामेम	0	0	0	0
5	भोजपुर	1654	1654	315	315
6	बाँसगंज-गंगा	0	0	0	0
7	इलाहाबाद	239	239	229	0
8	जौनपुर	17	17	0	0
9	बलिया	53	53	0	0
10	मधुबनी	4	4	0	0
11	मधुबनी	85	6	0	0
12	मधुबनी	504	0	0	0
13	बलिया	531	531	0	0
14	मधुबनी	359	359	0	0
15	बलिया	57	57	0	0
16	बलिया	0	0	0	0
17	बलिया	0	0	0	0
18	बाँसगंज	2219	147	147	0
19	मधुबनी	88	88	0	0
20	बलिया	274	274	0	0
21	बलिया	235	0	0	0
22	बलिया	21	21	0	0
23	बलिया	74	0	0	0
24	कुशी	38	38	0	0
कुल		6817	3831	752	322

612

State wise details of claims received, titles distributed and the extent of forest land for which titles distributed (individual and community), as on 30.04.2017, in major States, is indicated below:

States	No. of Claims received upto 30.04.2017			No. of Titles Distributed upto 30.04.2017			Extent of Forest land for which titles distributed (in acres)		
	Individual	Community	Total	Individual	Community	Total	Individual	Community	Total
Andhra Pradesh	1,69,088	4,711	1,73,799	85,678	1,415	87,093	2,02,420.00	4,41,061.00	6,43,481.00
Assam	1,48,965	6,046	1,55,011	57,325	1,477	58,802	NA	NA	NA
Bihar	8,022	0	8,022	121	0	121	NA	0.00	NA
Chhattisgarh	8,43,539	25,977	8,69,516	3,73,718	12,714	3,86,432	8,06,331.00	13,92,270.45	21,98,601.45
Goa	9,372	361	9,733	0	3	3	0.00	4.35	4.35
Gujarat	1,82,869	7,187	1,90,056	80,535	3,488	84,023	1,24,883.46	11,46,230.59	12,71,114.05
Himachal Pradesh	591	68	659	0	7	7	0.00	4,670.28	4,670.28
Jharkhand	99,224	3,286	1,02,510	54,458	1,723	56,181	98,265.22	45,503.71	1,43,768.93
Karnataka	2,98,795	5,741	3,04,536	12,421	628	13,049	16,436.60	26,465.31	42,901.91
Kerala	36,140	1,395	37,535	24,599	NA	24,599	33,018.12	NA	33,018.12
Madhya Pradesh	5,74,902	39,816	6,14,718	2,11,420	27,422	2,38,842	7,93,136.20	13,02,163.57	20,95,299.76
Maharashtra	3,52,950	11,408	3,64,358	1,06,898	5,748	1,12,646	5,77,026.20	44,35,944.77	50,12,970.97
Odisha	6,12,365	13,433	6,25,798	4,05,897	5,891	4,11,788	6,08,246.76	2,86,502.70	8,94,749.46
Rajasthan	70,515	688	71,203	36,183	72	36,255	55,116.12	485.84	55,601.96
Tamil Nadu	18,420	3,361	21,781	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Telangana	1,83,107	3,427	1,86,534	93,494	721	94,215	3,00,092.00	4,54,055.00	7,54,147.00
Tripura	1,98,238	277	1,98,515	1,25,020	55	1,25,075	4,35,726.57	91.16	4,35,817.74
Uttar Pradesh	92,520	1,124	93,644	17,712	843	18,555	18,854.46	1,20,802.06	1,39,656.53
Uttarakhand	182	0	182	0	0	0	0.00	0.00	0.00
West Bengal	1,31,962	10,119	1,42,081	44,444	686	45,130	21,014.27	572.03	21,586.29
<b>TOTAL</b>	<b>40,31,766</b>	<b>1,38,425</b>	<b>41,70,191</b>	<b>17,29,923</b>	<b>62,893</b>	<b>17,92,816</b>	<b>40,90,567</b>	<b>96,56,823</b>	<b>137,47,389.80</b>



परिशिष्ट-3

सामुदायिक वन अधिकार प्रकरणों की प्रगति दिनांक 31.03.2017 की स्थिति में

क्र.	जिला	प्राप्त/प्रेषित दावों की संख्या		अनुमोदित दावे की संख्या			वितरण किए गए वन अधिकार पत्र			वितरित मूगि (हेक्टेयर में)			निरस्त प्रकरणों की संख्या		
		एस.टी.	ओ.टी. एफ.डी.	एस.टी.	ओ.टी. एफ.डी.	योग	एस.टी.	ओ.टी. एफ.डी.	योग	एस.टी.	ओ.टी. एफ.डी.	योग	एस.टी.	ओ.टी. एफ.डी.	योग
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	बस्तर	2421	0	1890	0	1890	1890	0	1890	491.159	0	491.159	531	0	531
2	धमतरी	1198	180	1198	180	1378	1198	180	1378	98750.536	47938.405	146688.961	0	0	0
3	कोण्डागाव	3536	0	1464	0	1464	1317	0	1317	34391.39	0	34391.390	2072	0	2072
4	कोरिया	1065	5	1029	5	1034	1029	5	1034	3356.888	3.72	3340.608	36	0	36
5	सूरजपुर	1279	0	1258	0	1258	868	0	868	4511.64	0	4511.6	21	0	21
6	कांकेर	1283	0	779	0	779	779	0	779	121734.11	0	121734.110	804	0	804
7	राजनादगाव	825	0	772	0	772	772	0	772	45574.613	0	45574.61	53	0	53
8	बीजापुर	733	0	733	0	733	733	0	733	10544.848	0	10544.848	0	0	0
9	जशपुर	2626	1	2416	0	2416	657	0	657	1996.944	0	1996.944	210	1	211
10	रायगढ़	1560	4	1560	4	1564	609	4	613	702.824	3.724	706.548	0	0	0
11	सूकमा	519	0	519	0	519	481	0	481	26294.762	0	26294.76	0	0	0
12	कोरिया	1738	0	421	0	421	421	0	421	48676.503	0	48676.503	1317	0	1317
13	गुरियाबंद	445	17	263	14	377	363	14	377	38842.71	417.05	39259.760	85	1	88
14	बिलासपुर	525	25	291	20	311	291	20	311	182.376	4.652	187.028	234	5	239
15	भुमेली	388	142	166	126	292	166	126	292	218.112	106.281	324.393	22	16	38
16	सरगुजा	1327	131	404	29	433	261	29	290	44217.388	4844.366	49061.75	923	102	1025
17	दत्तेवाड़ा	913	0	211	0	211	211	0	211	201.5	0	201.500	57	0	57
18	नासबधपुर	539	0	180	0	180	180	0	180	6648.92	0	6648.920	359	0	359
19	बलीदावाजार	177	263	77	89	166	77	89	166	7341.18	3127.22	10468.400	100	174	274
20	वल्लभपुर	2689	6	2454	4	2458	158	4	162	2699.538	1.433	2700.971	233	2	235
21	महासमुद्र	0	188	0	161	161	0	161	161	0	15989.51	15989.51	0	4	4
22	कबीरघास	114	0	97	0	97	97	0	97	7550.95	0	7550.950	17	0	17
23	बालीद	168	0	94	0	94	94	0	94	60.746	0	60.75	74	0	74
24	जाजगीर-चापा	0	10	0	10	10	0	10	10	0	1140.777	1140.777	0	0	0
	महायोग	25871	972	18376	642	19018	12652	642	13294	504969.657	73577.138	578546.795	6848	307	7138